एफसीएनआर जमा ने बनाया नया रिकॉर्ड

30 सितंबर तक एफसीएनआर (बी) जमा 65-70 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली, 27 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेष एफसीएनआर (बी) जमा योजना को अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है.

एसबीआई रिसर्च की सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर (बी) जमा में महज 45 दिनों के भीतर ही वर्ष 2013 में तीन महीनों के दौरान जुटाए गए 26 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है. रिपोर्ट का अनुमान है कि यदि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 30 सितंबर 2026 तक एफसीएनआर (बी) जमा 65 से 70 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है,

जबकि कुल विदेशी मुद्रा जमा 80 से 85 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है. एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष ने बताया कि 17 जुलाई 2026 तक एफसीएनआर (बी) के तहत 17.4 अरब डॉलर की जमा राशि जुटाई जा चुकी है. कुल पूंजी प्रवाह 20 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान एफसीएनआर (बी) जमा का रहा.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भारतीय समुदाय का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त और सितंबर 2026 में परिपक्व होने वाली बड़ी मात्रा में मौजूदा एफसीएनआर जमा को नई योजना के तहत अधिक आकर्षक ब्याज दरों के कारण दोबारा निवेश किए जाने की संभावना है. इससे जमा राशि में और तेजी आने की उम्मीद है. एसबीआई का अनुमान है कि मौजूदा आधारभूत अनुमान के अतिरिक्त करीब 10 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि भी जुटाई जा सकती है, जिसका बड़ा हिस्सा उन देशों से आने की संभावना है जहां कर संबंधी रियायतें उपलब्ध हैं. रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है.

> पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप को सीमित बताया गया है. एसबीआई का मानना है कि रुपये की दीर्घकालिक मजबूती बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते तनाव और अस्थिर पूंजी प्रवाह जैसे बाहरी झटकों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनी रहे.

केनरा बैंक का मुनाफा एनपीए घटा

नई दिल्ली, 27 जुलाई सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए 4,856 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 4,752 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग दो प्रतिशत अधिक है. बैंक की आय, ब्याज आय और परिचालन लाभ में वृद्धि के साथ-साथ संपत्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. बैंक की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, बेहतर ऋण वसूली और घटते खराब ऋणों ने तिमाही परिणामों को मजबूती दी है.

जून तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 39,684 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 38,063 करोड़ रुपये थी.

संकट में भी महंगाई पर सरकार का काबू

सरकार ने पहले से रखे वित्तीय संसाधनों से कीमतों पर लगाम लगाई

युद्ध और कमजोर मानसून के बावजूद बजट में संशोधन की जरूरत नही

नई दिल्ली, 27 जुलाई. वेस्ट एशिया में जारी युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़ते दबाव और कमजोर मानसून जैसी चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने देश में महंगाई को नियंत्रण में रखने में सफलता हासिल की है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करते समय संभावित वैश्विक संकटों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश पहले से ही निर्धारित कर ली थी. इसी रणनीति के कारण पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और अन्य

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत का पूरा बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार को बजट में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है. एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों पर बीमा प्रीमियम और परिवहन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी आई.

> हालांकि, वैश्विक हालात का असर सरकारी खर्च पर भी दिखाई दे रहा है. बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण उर्वरक सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी और पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है. इसके बावजूद वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और आम नागरिकों को महंगाई से राहत देने की नीति आगे भी जारी रहेगी.

कच्चे तेल की कीमत लुढ़कने से घटा तनाव

डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और मुरबन सभी सस्ते हुए

तनाव घटा, लेकिन आपूर्ति जोखिम अभी बरकरार

नई दिल्ली, 27 जुलाई मध्य-पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संकेत मिलते ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 7 प्रतिशत तक की कमी आई और कई बेंचमार्क कच्चे तेल के दाम 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए.

हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में कुछ सुधार भी देखने को मिला. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा लगातार दूसरी रात ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने और क्षेत्र में तनाव कम होने से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं घटी हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बना. केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया के अनुसार, अमेरिका ने शुक्रवार रात से ही ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए थे. वहीं, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई सीमित करने के संकेत दिए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ओमान के साथ बातचीत शुरू की है. इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत का माहौल बना है. हालांकि, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरामको की ऊर्जा परियोजनाओं पर हमले का दावा किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में भू-राजनीतिक जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं.

सोमवार सुबह के कारोबार में अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 4.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.55 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया.

> डब्ल्यूटीआई अमेरिका में उत्पादित होता है, ब्रेंट उत्तरी सागर क्षेत्र का प्रमुख कच्चा तेल है, जबकि मुरबन अबू धाबी में उत्पादित होता है और एशियाई देशों में इसकी सबसे अधिक मांग रहती है. जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में मध्य-पूर्व की स्थिति और वैश्विक आपूर्ति से जुड़े घटनाक्रम ही कच्चे तेल की कीमतों की अगली दिशा तय करेंगे

पीएफ खातों में ब्याज जमा होना शुरू

नई दिल्ली, 27 जुलाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. देशभर के लाखों खाताधारकों को ब्याज की राशि उनके पीएफ खाते में जमा होने लगी है और कई सदस्यों को इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी मिल रही है. हालांकि, जिन खाताधारकों को अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है और सभी खातों में राशि क्रमश: जमा की जा रही है.

जबरदस्त वापसी, सेंसेक्स-निफ्टी में बड़ी तेजी

776 अंक चढ़ा सेंसेक्स

228 अंक की बढ़त पर रहा निफ्टी

मुंबई, 27 जुलाई पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार ने शानदार वापसी की. निवेशकों की मजबूत खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स 776.01 अंकों की तेजी के साथ 76,835.78 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी-50 228.50 अंक चढ़कर 23,995.95 के स्तर पर पहुंच गया.

कारोबार के दौरान बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत होता नजर

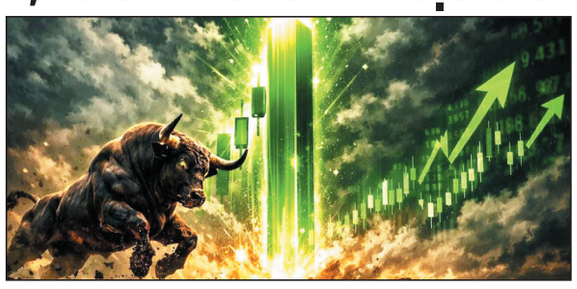

आया. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत, चुनिंदा बड़ी कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे और निचले स्तरों पर हुई खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के शेयरों में अच्छी मांग देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को समर्थन मिला.

> बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों ने मजबूत बुनियादी स्थिति वाली कंपनियों में खरीदारी का अवसर तलाशा, जिससे बाजार को मजबूती मिली. कारोबार के दौरान बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. आईटी क्षेत्र में भी खरीदारी का माहौल रहा, जबकि चुनिंदा उपभोक्ता और ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार की नजर बनी रही.

आईटीआर में भूल हुई तो नोटिस तय समझिए

नई दिल्ली, 27 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करते समय की गई छोटी-सी लापरवाही भी आयकर विभाग के नोटिस का कारण बन सकती है. तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली के कारण अब बैंक खाते, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड और संपत्ति से जुड़े लेनदेन का मिलान सीधे करदाता के रिटर्न से किया जाता है.

ऐसे में आय छिपाना या गलत जानकारी देना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान नहीं रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और सावधानी के साथ रिटर्न दाखिल करने से नोटिस की आशंका काफी हद तक कम की

जा सकती है. सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती गलत आईटीआर फॉर्म का चयन है. केवल वेतन, एक मकान और बैंक ब्याज से 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को आईटीआर-1 भरना चाहिए, जबकि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्ति बिक्री या पूंजीगत लाभ होने पर आईटीआर-2 आवश्यक होता है. व्यवसाय और पेशेवर आय वाले करदाताओं के लिए आईटीआर-3 या आईटीआर-4 निर्धारित हैं.

केवाईसी ठगी पर आरबीआई का अलर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अपडेट के नाम पर बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इन दिनों साइबर अपराधी बैंक खाते को बंद करने की चेतावनी देकर फर्जी एसएमएस और व्हाट्सऐप संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में एक लिंक दिया जाता है और दावा किया जाता है कि यदि तुरंत केवाईसी अपडेट नहीं किया गया तो बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा. घबराहट में कई लोग इस लिंक पर क्लिक कर अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा कर देते हैं, जिसके बाद उनके बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती है.

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक केवाईसी अपडेट कराने के लिए एसएमएस, व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता.

आईडीएफसी फर्स्ट पर बढ़ा भरोसा

नई दिल्ली, 27 जुलाई जून तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग देखने को मिली है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए उसका लक्ष्य मूल्य 73 से बढ़ाकर 95 प्रति शेयर कर दिया है. वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कई प्रमुख ब्रोकरेज संस्थानों ने लक्ष्य मूल्य में कटौती की है.

एसबीआई ने पीसीआई के साथ की साझेदारी

मुंबई, 27 जुलाई भारत की सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आज भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा की है.

एसबीआई लाइफ 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीजन के लिए भारतीय दल का प्रिंसिपल पार्टनर बन गया है. कंपनी आगामी ग्लासगो राष्ट्रमंडल पैरा खेल 2026 और आइची-नागोया (जापान) में होने वाले एशियाई पैरा खेल 2026 में जाने वाले भारतीय पैरालंपिक दल के लिए ऑफिशियल लाइफ

इंश्योरेंस पार्टनर होगी. एसबीआई लाइफ ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के दौरान भारत के पैरा-एथलीट्स के साथ अपने सफल सहयोग को आगे बढ़ाया है. कंपनी ने खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प, उनकी तैयारी और उत्कृष्टता की उन कहानियों को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो लोगों को आत्मविश्वास के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं.

इस साझेदारी के जरिए एसबीआई लाइफ का मकसद भारत के बेहतरीन पैरा-खिलाड़ियों की मेहनत और उनके सफर को पहचान देना और उसे दुनिया के सामने लाना है. ये एथलीट्स अपने पक्के इरादे और लगन से यह साबित कर रहे हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है. उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि यदि इंसान के पास आत्मविश्वास हो, सही तैयारी हो और अपनों का साथ मिले, तो वह किसी भी सपने को सच कर सकता है.

समाचार विशेष

देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की करेंगे राजनीति?

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भविष्य को लेकर पिछले कई हफ्तों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थीं. अंदरखाने यही सवाल था कि क्या उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा या वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

इस तरह की चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर एक संदेश भेजा दिया. जिसके बाद अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं. 22 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस 56 साल के हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. लेकिन चर्चा सिर्फ बधाई की नहीं हुई. मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा. बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस एक लाइन ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है. पिछले कुछ समय से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. महायुति के भीतर भी इसको लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही थीं. विपक्ष भी दावा कर रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में नेतृत्व बदल सकती है. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का यह संदेश काफी अहम माना जा रहा है.

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सामान्य जन्मदिन संदेश दो लाइन का होता है. लेकिन प्रधानमंत्री ने खास तौर पर फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास की बात लिखी. पार्टी के भीतर इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और फिलहाल दिल्ली जाने की कोई योजना नहीं है.

चुनौतियां अभी बाकी हैं

नेतृत्व को लेकर तस्वीर भले साफ होती दिख रही हो, लेकिन फडणवीस के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं. राज्य के कई शहरों में सीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून और संविधान की मर्यादा भी जरूरी है. गृह मंत्री होने के कारण सरकार की कार्रवाई पर भी सबकी नजर रहेगी.

डिजिटल युग में विरोध की नई राजनीति

सोशल मीडिया बना लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणक्षेत्र

नई दिल्ली. पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति और जन आंदोलनों का स्वरूप तेजी से बदला है. कभी विरोध-प्रदर्शन का असर सड़कों, धरनों और जनसभाओं तक सीमित होता था, लेकिन आज किसी भी आंदोलन की असली लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है.

चाहे वह चुनावी अभियान हो, सरकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो या युवाओं का कोई आंदोलन, हर पक्ष सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी

स्थापित करना चाहता है. हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर हुए युवा आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, वाट्सएप केवल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक संवाद और जनमत निर्माण के सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं. आज जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो, पोस्ट, रील्स और ग्राफिक्स वायरल होने लगते हैं.

> हाल के युवा आंदोलनों में भी यही देखने को मिला. अलग-अलग राजनीतिक दलों और आंदोलनकारी समूहों ने अपने-अपने एजेंडे के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग किया. किसी ने खुद को युवाओं का सबसे बड़ा समर्थक बताया, किसी ने विरोधियों पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया, तो किसी ने पूरे आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताने की कोशिश की.

लापरवाही नहीं, हर चाल पर नजर

विपक्ष पर वार की भाजपा की रणनीति

लखनऊ. भाजपा अपनी कमजोर कड़ियां दुरुस्त करने के साथ ही विपक्षी दलों की रिपोर्ट भी तैयार कर रही है. वह पता कर रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों का क्या कमजोर और क्या मजबूत पक्ष है. पार्टी की तैयारी है कि इस रिपोर्ट तैयार करके विपक्ष का ठीक से काउंटर किया जा सके.

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी की सबसे पहली कोशिश है कि जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना. इसके लिए हाल ही में हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ सम्मेलन आयोजित किए गए. इन सम्मेलनों में बूथ पदाधिकारियों की कड़ी परीक्षा ली गई. गैरहाजिर बूथ अध्यक्षों की जांच करवाई गई कि वे किस वजह से नहीं आए. कहा गया कि गैरहाजिरी का उचित कारण न हो तो उनको बदल दिया जाए. बूथ पदाधिकारियों को सभी सक्रिय और सामान्य सदस्यों की लिस्ट, पन्ना प्रमुखों की लिस्ट, पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की लिस्ट और क्षेत्र के प्रमुख लोगों की लिस्ट लाने के लिए कहा गया. इस लिस्ट के बारे में उनसे सवाल पूछे गए.

बूथ सम्मेलनों में उनको अपने क्षेत्र के दलित पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. साथ ही विपक्ष के मजबूत प्रत्याशियों और दावेदारों की लिस्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है.

दरअसल, पार्टी विपक्षी दलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है. इसमें वह पता लगा रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष की क्या तैयारी है. उसका क्या मजबूत और कमजोर पक्ष है. हर विधानसभा क्षेत्र में इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. इस रिपोर्ट में पता लगाया जाएगा कि विपक्ष क्या मुद्दे उठा सकता है, किन जातीय समीकरणों पर काम कर रहा है? कौन-कौन विधान सभा चुनाव के लिए विपक्ष में मजबूत दावेदार हैं.

फूलप्रूफ रणनीति की तैयारी

यह रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश स्तर तक भेजी जाएगी. इससे पार्टी विपक्ष की काट निकालने में मदद मिलेगी. मुद्दे और समीकरण पता होने पर उनमें पहले से सेंध लगाई जा सकेगी. वहीं, मजबूत दावेदारों का पता चलने पर पार्टी उन पर नजर रखेगी. पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट और तैयारी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान काफी काम आएगी. बूथ स्तर तक विपक्ष की तैयारी पता होगी तो उससे बेहतर रणनीति अपनी तैयार की जा सकेगी.

विशेष | **निरसा की राजनीति में नया राजनीतिक माहौल बना**

डेढ़ दशक बाद भाजपा में अशोक मंडल की वापसी

धनबाद. निरसा विधानसभा की राजनीति में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक मंडल की 16 साल बाद पार्टी में घर वापसी ने नया राजनीतिक माहौल बना दिया है.

लंबे समय बाद भाजपा में उनकी वापसी को संगठन के लिए बड़ी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से आने वाले दिनों में निरसा की राजनीति और भाजपा के भीतर संगठनात्मक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है. अशोक मंडल भाजपा के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. वे वर्ष 2007 से 2009 तक धनबाद ग्रामीण भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं. संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण निरसा क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. भाजपा में वापसी के साथ ही उन्होंने आगामी चुनावी तैयारियों की दिशा में सक्रियता बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि पार्टी 2029 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है और अशोक मंडल की वापसी उसी कड़ी का हिस्सा है. निरसा विधानसभा सीट भाजपा के लिए हमेशा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है.

पहले भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके

अशोक मंडल पहले भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पहचान है. उनके अनुभव का लाभ पार्टी को आगामी चुनावों में निश्चित रूप से मिलेगा. कुल मिलाकर, अशोक मंडल की भाजपा में घर वापसी ने निरसा की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पार्टी आने वाले समय में संगठन और चुनावी रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाती है तथा टिकट की दौड़ में कौन नेता बढ़त हासिल करता है.